रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पानी की नियमित व्यवस्था यद्यपि काफी नही है, फिर भी मेले के दिनो में रेलवे की ओर से पानी का खास इन्तजाम किया जाता है ताकि जहां तक हो सके तीर्थयात्रियों या दूसरे मुसाफिरो को असुविधा न हो ।

(ख) और (ग). एक नल-कूप (Tube well) बनाने की मजूरी दी गयी थी और रेलवे ने उस पर काम शुरू किया था । रेलवे के पास जो उपस्कर (equipment) थे उनसे कई जगह नलकूप लगाने की कोशिश की गयी, लेकिन नीचे की जमीन पथरीली होने की वजह से सफलता नही मिली । अब नल-कूप लगाने के लिये विशेष उपस्कर का इन्तजाम करने का विचार है ।

नलकूप लगाने पर २७,६७६ रुपये की लागत का अनुमान है, जिसमें से अब तक ७,१०० रुपये खर्च हो चुके है ।

रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था

१०३. श्री मोहन स्वरूप : क्या रेलवे मंत्री निम्नलिखित बातें दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे .

(क) सारे भारत में कितने ठेकेदारों के ठेके विभागीय भोजन व्यवस्था के अधीन समाप्त कर दिये गये और उनमें से कितने बेकार हैं और कितनों को काम दिया जा चुका है ; और

(ख) विभागीय व्यवस्था के लिये रेलवे प्रशासन को दिल्ली, बम्बई और मद्रास आदि जैसे बड़े जंकशन स्टेशनों पर कितने कर्मचारी रखने पड़ते हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) एक बयान रक्खी है [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५२]

(ख)

जंकशन का नाम	नियुक्त कर्मचारियों की तादाद
वाल्टेर	१७
बंगलूर सिटी	३३
मुगलसराय	७८
हावड़ा	१७०
सियालदह	७७
गोरखपुर	८८
बम्बई	३१९
पूना	१०४
नागपुर	८४
झासी	८०
बिलासपुर	२६
कटक	३४
अजमेर ज०	३१
मेहसाना	५०
रतलाम ज०	५२
गौहाटी	३४
दिल्ली	१५४
नयी दिल्ली	५८

नोट — मद्रास एग्मोर और मद्रास सेन्ट्रल स्टेशनो पर विभागी खान-पान व्यवस्था नही है । इन स्टेशनो पर खान-पान व्यवस्था ठेकेदारो के हाथ में है ।

पूर्वोत्तर रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था

१०४. श्री मोहन स्वरूप : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ जंकशन (चारबाग) और सिटी स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर विभागीय भोजन व्यवस्था आरम्भ कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका रेलवे के कितने ठेकेदारों पर प्रभाव पड़ा है ;

(ग) रेलवे के कितने ठेकेदारों के ठेके विभागीय भोजन व्यवस्था के अधीन बन्द

कर दिये गये हैं और कितने ठेकेदारों को अपना कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई है ;

(घ) क्या ऐसे सब ठेकेदारों को जिनके ठेके समाप्त कर दिये गये थे, अन्य रेलवे स्टेशनों पर काम दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ सिटी स्टेशन पर विभागी खान-पान व्यवस्था (Departmental catering) शुरू नहीं की गयी है और न यह व्यवस्था वहां शुरू करने का कोई विचार है । लेकिन उत्तर रेलवे के लखनऊ (चारबाग) स्टेशन (बड़ी लाइन) और पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ जं० (मीटर लाइन) स्टेशन पर विभागी खान-पान व्यवस्था शुरू कर दी गयी है ।

(ख) नौ ।

(ग) आठ ठेकेदारों के ठेके खत्म कर दिये गये हैं और एक ठेकेदार के ठेके में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है ।

(घ) और (ङ). जिन आठ ठेकेदारों के ठेके खत्म किये गये हैं उनमें से तीन को दूसरे स्टेशनों पर ठेके नहीं दिये गये, क्योंकि उनके पास जो दूसरे ठेके हैं उन्हें ही काफी समझा गया है ।

बाकी चार ठेकेदारों में से तीन ने दूसरे स्टेशनों पर ठेके मंजूर कर लिये हैं और काम चालू कर दिया गया है । एक ठेकेदार ने दूसरे स्टेशन पर ठेका लेना अभी मंजूर नहीं किया है और वहां काम शुरू नहीं हुआ है । एक ठेकेदार को दूसरे स्टेशन पर ठेका दिया गया था । वह ठेका अभी खाली नहीं है क्योंकि उसके बारे में अदालत ने निषेध-आदेश (injunction) दे रखा है ।

आवारा पशु पकड़ने की योजना

१०५. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवारा पशु पकड़ने की योजना के अन्तर्गत दिल्ली और भारत के अन्य भागों में अब तक कितने पशु पकड़े गये ;

(ख) इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की गयी ;

(ग) इन पशुओं को बेचने से कितनी आय हुई ; और

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली में पकड़े गये बहुत से पशु पुरानी दिल्ली के अनेक कांजी हौसों में केवल १० या ११ रुपये पर नीलाम कर दिये जाते हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) से (ग). यह योजना केवल दिल्ली और जम्मू व काश्मीर राज्य में चालू है । ब्योरे का एक विवरण नत्थी कर दिया गया है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५३**]

(घ) जी हां । दिल्ली जिले के मेजिस्ट्रेट ने कांजी हौस के प्रति पशु की नीलामी की कीमत कम से कम १० रुपये रखी है ।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड के अन्तर्गत महिला कल्याण योजना

१०६. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड के अन्तर्गत महिला कल्याण योजना द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने में कितनी सफलता हुई :